अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग
GRANT No. 13 - DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपए में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	38475,54,00			
			60957,16,00	52867,14,01	-8090,01,99
पूरक	Supplementary	22481,62,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				719,93,31
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	93152,44,00			
			94147,51,00	78992,33,26	-15155,17,74
पूरक	Supplementary	995,07,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10626,71,72

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (₹809001.99 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹2248162.00 लाख के पूरक अनुदान का 36 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of grant, the overall savings (₹809001.99 lakhs) constituted 36 percent of the supplementary grants of ₹2248162.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 13 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	95883.00			
पू.	S.	27358.00	123252.36	100919.58	- 22332.78
पु.	R.	11.36			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pension and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	1751000.00			
पू.	S.	180100.00	1930594.50	1822772.96	-107821.54
पु.	R.	-505.50			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	106000.00			
			101000.00	..	-101000.00
पु.	R.	-5000.00			
मुख्य शीर्ष "3275"	Major Head "3275"				
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services				
मू.	O.	1894631.00			
पू.	S.	2040704.00	3868864.77	3363010.42	-505854.35
पु.	R.	-66470.23			

(I) मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत ₹106000.00 लाख का प्रावधान दो मामलों में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹106000.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under Major Head "2552" under the following heads:-

(का) "अन्य संचार सेवाएं – वैश्विक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा – अन्य संचार सेवाएं – वैश्विक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा" – ₹101000.00 लाख उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए यूएसओएफ परियोजना हेतु कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण।

(A) "Other Communication Services - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Other Communication Services - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - ₹101000.00 lakhs - due to requirement of less funds towards USOF project for North Eastern Region.

(खा) "अन्य व्यय – टेलीमैटिक्स विकास केंद्र" – ₹5000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण।

(B) "Other Expenditure - Centre for Development of Telematics" - ₹5000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilized as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" –

(A) Major Head "3451" -

(क) "सचिवालय – संचार मंत्रालय" – ₹998.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹138.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1136.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹431.90 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन, पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई), छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Secretariat - Ministry of Communications" - the original provision of ₹998.00 lakhs was augmented to ₹1136.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹138.00 lakhs. However, there was a saving of ₹431.90 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards salaries, FTE, LTC and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "संबद्ध कार्यालय" –

(b) "Attached Offices" -

(i) "दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र" – ₹4600.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹782.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5382.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1550.38 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन, भत्ते, व्यावसायिक सेवाओं और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(i) "Telecommunications Engineering Centre" - the original provision of ₹4600.00 lakhs was augmented to ₹5382.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹782.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1550.38 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards

salaries, allowances, professional services and other establishment related expenses.

(ii) "रखरखाव" – ₹275.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹158.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹433.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹195.97 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) लघु सिविल और इलेक्ट्रिक कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) "Maintenance" - the original provision of ₹275.00 lakhs was augmented to ₹433.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹158.00 lakhs. However, there was a saving of ₹195.97 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards minor civil and electric works.

(iii) "सतर्कता दूरसंचार निगरानी प्रकोष्ठ" – ₹23272.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5857.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹29129.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹6058.11 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन और अन्य स्थापना व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iii) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" - the original provision of ₹23272.00 lakhs was augmented to ₹29129.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5857.00 lakhs. However, there was a saving of ₹6058.11 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards salaries and other establishment expenses.

(iv) "राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी)" – ₹3512.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹411.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3923.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹563.80 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन और अन्य स्थापना व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(iv) "National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training (NTIPRIT)" - the original provision of ₹3512.00 lakhs was augmented to ₹3923.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹411.00 lakhs. However, there was a saving of ₹563.80 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards salaries, other establishment expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(v) "राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान" – ₹1359.00

(v) "National Institute of Communication

लाख के मूल प्रावधान को ₹188.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1547.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹472.02 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

Finance" - the original provision of ₹1359.00 lakhs was augmented to ₹1547.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹188.00 lakhs. However, there was a saving of ₹472.02 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(खा) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल – ग्रेच्युटी – साधारण पेंशन" – ₹212856.60 लाख के मूल प्रावधान को ₹722.10 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹213578.70 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹68900.66 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) पेंशन संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) Major Head "2071" - "Civil - Gratuities - Ordinary Pensions" - the original provision of ₹212856.60 lakhs was augmented to ₹213578.70 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹722.10 lakhs. However, there was a saving of ₹68900.66 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards pensionary charges.

(गा) मुख्य शीर्ष "3275" –

(क) "प्रशिक्षण – दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण" – ₹136.10 लाख के मूल प्रावधान को ₹131.80 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹267.90 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹226.53 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अनुसंधान/अनुसंधान विकास – प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश संवर्धन" – ₹3446.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2137.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त कर बढ़ाकर ₹5583.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹3245.68 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हैकाथॉन के लिए प्रयोगशालाओं के उपयोग हेतु भुगतान स्थगित किए जाने और टीएसडीएसआई को भुगतान स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "अन्य व्यय – भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण" – ₹10000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1500.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके

(C) Major Head "3275" -

(a) "Training- Training to DoT Officers" - the original provision of ₹136.10 lakhs was augmented to ₹267.90 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹131.80 lakhs. However, there was a saving of ₹226.53 lakhs (including supplementary grant) - due to conduction of less training programmes.

(b) "Research/Research Development - Technology Development and Investment Promotion" - the original provision of ₹3446.00 lakhs was augmented to ₹5583.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2137.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3245.68 lakhs (including supplementary grant) - due to postponement of payment for use of Labs for Hackathon and non-approval of payment to TSDSI.

(c) "Other Expenditure - Telecom Regulatory Authority of India" - the original provision of ₹10000.00 lakhs was augmented to

बढ़ाकर ₹11500.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1800.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) ट्राई के स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

₹11500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1500.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1800.00 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards establishment related expenses of TRAI.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः—

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय" –

(क) "निदेशालय" – ₹33354.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹11342.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹44696.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, जो वेतन, किराया दरों और भूमि और भवन के लिए करों और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹10270.65 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(ख) "मुख्य शीर्ष 3201 – डाक सेवाओं में लेखापरीक्षा प्रभार के हिस्से के कारण हस्तांतरित राशि" – ₹300.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹365.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹665.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, जो डाक विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रभार के हिस्से के लिए कम दावों के कारण ₹300.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(ग) "संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय" – ₹20134.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4835.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹24969.00 लाख तक बढ़ाया गया, तथापि, जो वेतन और अन्य स्थापना शुल्कों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹3028.36 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(A) Major Head "3451" - "Attached Offices" -

(a) "Directorate" - the original provision of ₹33354.00 lakhs was augmented to ₹44696.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11342.00 lakhs. which, however, remained unutilized to the extent of ₹10270.65 lakhs - due to requirement of less funds towards salaries, Rent Rates and Taxes for land and building and other establishment related expenses.

(b) "Amount transferred to Major Head 3201 - Postal Services on account of share of Audit Charges" - the original provision of ₹300.00 lakhs was augmented to ₹665.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹365.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹300.00 lakhs - due to less claims by Postal Department towards share of audit charges.

(c) "Controller of Communication Accounts Offices" - the original provision of ₹20134.00 lakhs was augmented to ₹24969.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4835.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹3028.36 lakhs - due to requirement of less funds towards salaries and other establishment charges.

(घ) "संचार महालेखा नियंत्रक" – ₹1577.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹193.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1770.00 लाख तक बढ़ाया गया, तथापि, जो वेतन, भतों, मुद्रण एवं प्रकाशन और चिकित्सा उपचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹179.42 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(d) "Controller General of Communication Accounts"- the original provision of ₹1577.00 lakhs was augmented to ₹1770.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹193.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹179.42 lakhs - due to requirement of less funds towards salaries, allowances, printing, publication and Medical treatment.

(खा) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" –

(B) Major Head "2071" - "Civil" -

(क) "अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशन"– ₹1166796.30 लाख के मूल प्रावधान को ₹121991.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1288787.30 लाख तक बढ़ाया गया, तथापि, जो ₹7571.70 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया; और

(a) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - the original provision of ₹1166796.30 lakhs was augmented to ₹1288787.30 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹121991.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹7571.70 lakhs; and

(ख) "परिवार पेंशन – परिवार पेंशन" – ₹288352.70 लाख के मूल प्रावधान को ₹57147.30 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹345500.00 लाख तक बढ़ाया गया, तथापि, जो ₹5527.07 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Family Pensions- Family Pensions" - the original provision of ₹288352.70 lakhs was augmented to ₹345500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹57147.30 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹5527.07 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत पेंशन संबंधी प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

Savings under above two heads were due to requirement of less funds towards pensionary charges.

(गा) मुख्य शीर्ष "3275" –

(C) Major Head "3275" -

(क) "प्रशिक्षण" –

(a) "Training" -

(i) "संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान" – ₹609.70 लाख के मूल प्रावधान को ₹997.20 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1606.90 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, जो कुछ प्रत्याशित प्रशिक्षणों का आयोजन न किए जाने और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन

(i) "Training Institute for Communication Finance" - the original provision of ₹609.70 lakhs was augmented to ₹1606.90 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹997.20 lakhs which, however,

की कम संख्या होने के कारण ₹591.55 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(ii) "राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी)" – ₹454.20 लाख के मूल प्रावधान को ₹2921.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3375.20 लाख तक बढ़ाया गया था। तथापि, जो डीटीई, एफटीई, प्रशिक्षण व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और आईआईटी कानपुर में आईटीएस 2023 बैच के लिए प्रेरण प्रशिक्षण को स्थगित किए जाने के कारण ₹2904.79 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(ख) "आरक्षित निधि को अंतरण – वैश्विक सेवा दायित्व निधि को अंतरण" – ₹100000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹950000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1050000.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, जो वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण ₹330000.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(ग) "अन्य व्यय – दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण" – ₹2320.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹801.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3121.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, जो वेतन, किराया दरों और भूमि और भवनों के लिए करों और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹565.33 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

remained unutilized to the extent of ₹591.55 lakhs - due to non-conduction of certain anticipated trainings and lesser number of nominations for various training programmes.

(ii) "National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training (NTIPRIT)" - the original provision of ₹454.20 lakhs was augmented to ₹3375.20 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2921.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2904.79 lakhs - due to requirement of less funds towards DTE, FTE, Training expenses and postponement of induction training for ITS 2023 Batch at IIT Kanpur.

(b) "Transfer to Reserve Fund- Transfer to Universal Service Obligation Fund" - the original provision of ₹100000.00 lakhs was augmented to ₹1050000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹950000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹330000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Other Expenditure - Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal" - the original provision of ₹2320.00 lakhs was augmented to ₹3121.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹801.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹565.33 lakhs - due to requirement of less funds towards salaries, Rent Rates and Taxes for Land and Buildings and other establishment related expenses.

(IV) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "पेंशन का सरांशिकृत मूल्य – साधारण पेंशन" – ₹25514.92 लाख की बचत (₹76795.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "छुट्टी नकदीकरण लाभ– साधारण पेंशन" – ₹836.38 लाख की बचत (₹4018.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत, पेंशन संबंधी प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "वैश्विक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा" –

(क) "सेवा प्रदाताओं को मुआवजा" – ₹345170.43 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹781740.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(ख) "अनुसंधान और विकास के लिए मुआवजा" – ₹23992.99 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "उद्योगों / कंपनियों को सहायता" –

(क) "भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना" – ₹96240.69 लाख की बचत (₹180634.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीएलआई लाभार्थियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" - saving of ₹25514.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹76795.90 lakhs); and

(B) "Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions" - saving of ₹836.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4018.10 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards pensionary charges.

(V) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" -

(a) "Compensations to Service Providers" - saving of ₹345170.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹781740.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due to requirement of less funds towards project.

(b) "Compensations for R&D" - saving of ₹23992.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards R&D project.

(B) "Assistance to Industries/Companies" -

(a) "Production Linked Incentive (PLI) Scheme to Promote Telecom and Networking Products Manufacturing in India" - saving of ₹96240.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180634.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the PLI beneficiaries.

(ख) "दूरसंचार क्षेत्र के नवप्रवर्तन और भावी प्रौद्योगिकी के उद्भवन को बढ़ावा देने के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए प्रावधान" – ₹5140.00 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना बंद होने की वजह से ब्रांड बिल्डिंग योजना के तहत कम निधियों की आवश्यकता होने और डीसीआईएस योजना के तहत लाभार्थी कंपनियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Provision for Champion Service Sector Scheme for Promotion of Innovation and incubation of Future Technology of Telecom Sector" - saving of ₹5140.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to requirement of less funds under Brand Building Scheme owing to closure of the scheme and receipt of less claims from the beneficiaries' companies under DCIS scheme.

(गा) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता"–

(C) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings" -

(क) "गारंटी शुल्क की माफी" – ₹38661.00 लाख की बचत (₹55637.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीएसएनएल/एमटीएनएल से कम गारंटी शुल्क प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Waiver of Guarantee Fee" - saving of ₹38661.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55637.00 lakhs) was due to receipt of less Guarantee Fee from BSNL/MTNL.

(ख) "बांड पर ब्याज का भुगतान" – ₹926.14 लाख की बचत (₹31174.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमटीएनएल बांड पर ब्याज का भुगतान न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Payment of Interest on Bonds" - saving of ₹926.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31174.00 lakhs) was due to non-payment of interest on MTNL bonds.

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–वैश्विक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा" – ₹81836.71 लाख की बचत (₹83830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - saving of ₹81836.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹83830.00 lakhs);

(ड.) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – वैश्विक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा" – ₹17685.41 लाख की बचत (₹43430.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(E) "Tribal Area Sub-Plan - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - saving of ₹17685.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43430.50 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत यूएसओएफ योजना/परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

Savings under above two heads were due to requirement of less funds towards USOF Scheme/ project.

(चा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – आईटीयू क्षेत्रीय कार्यालय एवं नवाचार केंद्र" – ₹768.06 लाख की बचत (₹1340.00

(F) "International Co-operation - ITU Area Office & Innovation Centre" - saving of ₹768.06 lakhs

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईटीयू क्षेत्रीय कार्यालय के लिए संशोधित किराया दरों और सीएचएफ अंशदान चालान प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹422.42 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत है।

2.(I) उपर्युक्त बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय – केंद्रीय निगरानी प्रणाली – संचालन और रखरखाव" – ₹1021.79 लाख का अधिक व्यय (₹1397.90 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹5194.90 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मरम्मत और रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" –

(क) "स्वायत्त निकायों को सहायता – टेलीमैटिक्स विकास केंद्र" – ₹5000.00 लाख का अधिक व्यय (₹38700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों के पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों को वृद्धिशील पेंशन भुगतान" – ₹42624.24 लाख का अधिक व्यय (₹382215.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹382216.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों को वृद्धिशील पेंशन भुगतान के लिए अधिक दावों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

(against the sanctioned provision of ₹1340.00 lakhs) was due to revised rental rates for ITU area office and non-submission of CHF Contribution Invoice.

(VI) Under one head saving of ₹422.42 lakhs occurred constituting 29 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Attached Offices - Central Monitoring System - Operation and Maintenance" - excess of ₹1021.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5194.90 lakhs including supplementary grant of ₹1397.90 lakhs) was due to requirement of additional funds towards repair and maintenance.

(B) Major Head "3275" -

(a) "Assistance to Autonomous Bodies - Centre for Development of Telematics" - excess of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38700.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Assistance to Public Sector and other Undertakings-Incremental Pension Payment to voluntarily Retiring BSNL and MTNL Employees" - excess of ₹42624.24 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹382216.00 lakhs including supplementary grant of ₹382215.00 lakhs) was due to receipt of more claims towards Incremental Pension Payment to voluntarily Retiring BSNL and MTNL Employees.

(ग) "आरक्षित निधि को अंतरण – सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण" – ₹330000.00 लाख का अधिक व्यय (₹700000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों को ज्यादा अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(c) "Transfer to Reserve Fund - Additional transfer to Universal Service Obligation Fund" - excess of ₹330000.00 lakhs (against supplementary provision of ₹700000.00 lakhs) was due to more transfer of funds.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹464.26 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत है।

(II) Under one head excess of ₹464.26 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹1515517.74 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त ₹99507.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1515517.74 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹99507.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and constituted 16 percent of the sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas		85000.00	..	-85000.00
मुख्य शीर्ष "4859"	Major Head "4859"				
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	16800.00	5900.00	5900.00	..
पु.	R.	-10900.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5275"	Major Head "5275"				
अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	9197826.00			
पू.	S.	2.00	8146056.28	7778210.74	-367845.54
पु.	R.	-1051771.72			

(I) ₹86021.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹86000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹86021.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under four heads; of these ₹86000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "अन्य संचार सुविधाएं – भारत नेट" – ₹85000.00 लाख पूर्वोतर क्षेत्रों के लिए भारत नेट परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

(A) Major Head "4552" - "Other Communication Facilities - Bharat Net" - ₹85000.00 lakhs - due to requirement of less funds towards Bharat Net Project for North Eastern Region.

(खा) मुख्य शीर्ष "5275" – "अन्य व्यय – भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण" – ₹1000.00 लाख एनबीसीसी के साथ पंजीकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से भवन के लिए स्टांप शुल्क का भुगतान न किए जाने के कारण।

(B) Major Head "5275" - "Other Expenditure - Telecom Regulatory Authority of India" - ₹1000.00 lakhs - due to non-payment of stamp duty for building owing to non-finalization of registration process with NBCC.

(II) मुख्य शीर्ष "4859" – "दूरसंचार – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – आईटीआई पुनरुद्धार (इक्विटी निवेश)" – ₹10900.00 लाख की बचत (₹16800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(II) Under Major Head "4859" - "Telecommunications - Investment in Public Sector and other Undertakings - ITI Revival (Equity Investment)" - saving of ₹10900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16800.00 lakhs); and

(III) मुख्य शीर्ष "5275" –

(III) Under Major Head "5275" -

(का) "अन्य संचार सुविधाएं" –

(A) "Other Communication Facilities" -

(क) “वायरलेस योजना और समन्वय” – ₹8744.72 लाख की बचत (₹16324.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(ख) “भारत नेट” – ₹273425.52 लाख की बचत (₹657900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत नेट योजना/परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) “स्पूफ्ड इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल्स की रोकथाम प्रणाली (सीआईओआर)” – ₹2723.00 लाख की बचत (₹3876.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू वित्त वर्ष में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भुगतान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूंजीगत निवेश” – ₹1097617.60 लाख की बचत (₹8291620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – भारत नेट” – ₹70231.27 लाख की बचत (₹70550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भारत नेट” – ₹21842.37 लाख की बचत (₹36550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत भारत नेट योजना/परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(a) “Wireless Planning and Co-ordination” - saving of ₹8744.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16324.00 lakhs).

Saving under above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Bharat Net” - saving of ₹273425.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹657900.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Bharat Net Scheme/project.

(c) “Prevention of Spoofed Incoming International Calls System (CIOR)” - saving of ₹2723.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3876.00 lakhs) was due to non-payment for cloud infrastructure in the current financial year.

(B) “Investment in Public Sector and Other Undertakings - Capital Infusion in BSNL and MTNL” - saving of ₹1097617.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8291620.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Bharat Net” - saving of ₹70231.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70550.00 lakhs); and

(D) “Tribal Area Sub-Plan - Bharat Net” - saving of ₹21842.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36550.00 lakhs).

Saving under above two heads were due to requirement of less funds towards Bharat Net Scheme/project.

(ड.) “अन्य व्यय – डिजिटल आसूचना एकक परियोजना” – ₹1949.10 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्लाउड सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(E) “Other Expenditure - Digital Intelligence Unit Project” - saving of ₹1949.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards cloud services.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹829.30 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक किन्तु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक थी।

(IV) Under two heads, saving of ₹829.30 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 16 percent to 38 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचत (₹47123.50 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में मुख्य शीर्ष “5275” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:–

4.(I) The above savings were partly (₹47123.50 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2024 and March, 2025 under the Major Head “5275” under the following heads:-

(का) “प्रशिक्षण – राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी)” – ₹399.80 लाख।

(A) “Training - National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training (NTIPRIT)” - ₹399.80 lakhs.

(खा) “अन्य संचार सुविधाएं” –

(क) “निगरानी सेवाएँ” – ₹1423.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1428.45 लाख था।

(ख) “एकीकृत पोर्टल” – ₹500.40 लाख।

(B) “Other Communication Facilities” -

(a) “Monitoring Services” - ₹1423.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹1428.45 lakhs.

(b) “Unified Portal” - ₹500.40 lakhs.

(गा) “अन्य व्यय – रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क” – ₹44799.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹44622.92 लाख था।

(C) “Other Expenditure - OFC based network for Defence Services” - ₹44799.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹44622.92 lakhs.

(II) बचत मुख्य शीर्ष “5275” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the Major Head “5275” under following heads:-

(का) “प्रशिक्षण – संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान” – ₹836.41 लाख का अधिक व्यय (₹1058.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) “Training - Training Institute for Communication Finance” - excess of ₹836.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1058.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Building and Structures.

(खा) "अन्य व्यय – दूरसंचार कंप्यूटर आपातकालीन कार्य बल" – ₹10846.00 लाख का अधिक व्यय (₹854.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार दूरसंचार कंप्यूटर आपातकालीन कार्य बल (टी–सीईआरटी) के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

5. भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि:-

भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की स्थापना 28 मार्च, 1997 को भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी। भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 से इस प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ। भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण ने बेहतर गुणवता और वहनीय कीमत के साथ टेलीकाम क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगिता के लिए प्रयास किया है। नई टेलीफोन नीति 99 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 9 जनवरी 2004 की अधिसूचना के तहत प्रसारण और केबल सेवाएं भी भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण के दायरे में आ गई हैं। भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 2024–25 के लिए इसकी निधियों का ब्यौरा निम्न अनुसार है:–

(B) "Other Expenditure - Telecom Computer Emergency Response Team" - excess of ₹10846.00 lakhs (against sanctioned provision of ₹854.00 lakhs) was due to requirement of additional fund for Telecom Computer Emergency Response Team (T-CERT) as per Detailed Project Report (DPR).

5. Telecom Regulatory Authority of India General Fund:-

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 enacted on 28th March 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 09th January 2004, broadcasting and cable services have also come under the purview of TRAI. The Grants for TRAI is made by the Central Government.

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	53,12,21
प्राप्तियां	Receipts	99,48,85
अदायगियां	Payments	97,00,00
अंत शेष	Closing Balance	55,61,06

6. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि :-

नई टेलीकाम नीति, 99 (एनटीपी 99) में किफायती और उचित मूल्यों पर बेसिक टेलीकाम सेवाओं तक सभी की पहुच की परिकल्पना की गई है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसक्यू) को पूरा करने के लिए संसाधन सार्वभौमिक सेवा लेवी (यूएसएल) के माध्यम से सृजित किए जाएंगें जो विभिन्न लाइसेंसों के तहत आपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व का प्रतिशत होगा। सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस शुल्क (एलएफ़) के एक

6. Universal Service Obligation Fund:-

The New Telecom Policy, 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators

घटक के रूप में सार्वभौमिक सेवा लेवी (यूएसएल) का संग्रहण भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का आवंटन बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन से किया जाता है।

under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of License Fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per budgetary procedure.

वर्ष 2024–25 के लिए निधियों का लेखा निम्न अनुसार है:–

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	43619,50,28
प्राप्तियां	Receipts	18500,00,00
अदायगियां	Payments	8798,16,30
अंत शेष	Closing Balance	53321,33,98

7. गारंटी मोचन निधिः-

7. Guarantee Redemption Fund:-

सॉवरेन गारंटी बॉन्ड की सर्विसिंग के लिए सरकारी गारंटी के आह्वान पर एमटीएनएल को ऋण का भुगतान किया गया। सरकारी वित्तीय नियम, 2017 के नियम 283 के अनुसार, सरकारी गारंटी के आह्वान से संबंधित बुकिंग में सार्वजनिक लेखा शीर्ष 8235.00.117.00.00 – गारंटी मोचन निधि को शामिल किया जाना आवश्यक है। गारंटी मोचन निधि का प्राप्ति पक्ष विदेश कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

Loans were paid to MTNL on invocation of Government Guarantee towards servicing the Sovereign Guarantee Bonds. As per the Rule 283 of the Government Financial Rules, 2017, the public head of account 8235.00.117.00.00 - Guarantee Redemption Fund needs to be involved in the booking related to invocation of Government Guarantee. The receipt side of Guarantee Redemption Fund is operated by the Department of External Affairs, Ministry of Finance.

वर्ष 2024–25 के लिए निधि का लेखा–जोखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	शून्य NIL
प्राप्तियां	Receipts	शून्य NIL
अदायगियां	Payments	1151,22,56
अंत शेष	Closing Balance	-1151,22,56